आदिवासी विकास खंडों में आदिवासी विकास कार्यक्रम का बन्द होना

598. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय द्वारा आदिवासी विकास खंडों में चलाया गया आदिवासी विकास कार्यक्रम इस बीच रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है ;

(ग) क्या कोई वैकल्पिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है अथवा चलाने का विचार है जिससे विकास खण्ड के स्तर पर आदिवासियों का हितसाधन हो ; और

(घ) मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों के विकास के लिए किन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है और वर्ष 1976-77 में उससे क्या उपलब्धियां हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : पांचवीं योजना के दौरान, आदिवासी विकास खंड कार्यक्रम के बदले आदिवासी उप-योजना कार्यक्रम रखे गए है। 50 प्रतिशत या इससे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को चुन लिया गया है और इनके लिए आदिवासी उप-योजनाएं तैयार कर ली गई है। देशभर में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों को 178 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में बांट दिया गया है। प्रत्येक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के कार्यक्रम प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की समस्याओं पर आधारित है।

(घ) मध्य प्रदेश में, आदिवासी उप-योजना क्षेत्र को 42 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में बांट दिया गया है। 1976-77 के दौरान इन परियोजनाओं में विभिन्न सेक्टरों के अधीन योजनाओं संबंधी परिव्यय संलग्न में दिया गया है।

विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	विकास का शीर्ष	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता
1	कृषि व सम्बद्ध कार्यक्रम . . .	1225.00	661.00
2	सहकारिता	180.00	200.00
3	जल और विद्युत विकास . . .	943.00	—
4	उद्योग और खनिज . . .	115.00	50.00
5	परिवहन और संचार . . .	413.00	30.00
6	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं . .	1124.00	50.00
7	आर्थिक सेवाएं	—	20.00
	योग . . .	4000.00	1011.00